कर्नाटक का बड़ा फैसला: स्कूलों में छात्राओं की अनिवार्य चिकित्सा जाँच, CCTV और बाल संरक्षण समितियाँ



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

स्कूली बच्चों - विशेषकर छात्राओं - की सुरक्षा को लेकर उठती चिंताओं के बीच **कर्नाटक सरकार** ने राज्य के सभी स्कूलों (सरकारी, अनुदानित और निजी) के लिए बाल-सुरक्षा संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर एक **परिपत्र** पारित किया है। इसमें छात्राओं की अनिवार्य चिकित्सा जाँच, लैंगिक शिक्षा, CCTV, शिकायत-पेटियाँ और परामर्शदाताओं की व्यवस्था जैसे प्रावधान शामिल हैं।

परिपत्र के प्रमुख प्रावधान

- **स्वास्थ्य-जाँच:** छात्राओं के लिए स्कूलों में अनिवार्य स्त्रीरोग संबंधी (गाइनेकोलॉजिकल) चिकित्सा जाँच की व्यवस्था; साथ ही आयु-उपयुक्त लैंगिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्देश।
- **निगरानी:** स्कूल परिसरों में CCTV कैमरे अनिवार्य; परिसर में प्रवेश-निकास पर नज़र रखने की व्यवस्था।
- **संस्थागत तंत्र:** हर स्कूल में **बाल संरक्षण समिति** (Child Protection Committee) - जिसकी बैठक तिमाही आधार पर होगी; शिकायत-पेटियाँ और प्रशिक्षित परामर्शदाता (काउंसलर) नियुक्त करने होंगे।
- **अनुपस्थिति-ट्रैकिंग:** कोई छात्रा लगातार तीन दिन अनुपस्थित रहे तो स्कूल को ग्राम पंचायत और चाइल्ड हेल्पलाइन **1098** को सूचित करना होगा - बाल विवाह और तस्करी की रोकथाम के लिए।
- **कानूनी जागरूकता:** पोक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 पर विद्यार्थियों-अभिभावकों-शिक्षकों को जागरूक करना; लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

यह परिपत्र बाल अधिकारों के संस्थागत क्रियान्वयन का उदाहरण है - **NCPCR** (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, CPCR अधिनियम 2005 के तहत), **पोक्सो अधिनियम 2012**, **चाइल्ड लाइन 1098** (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन) और राज्य स्तर पर स्कूल-शिक्षा विभाग की भूमिका एक साथ जुड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 21A, 24 और 39(e)-(f) बाल संरक्षण के संवैधानिक आधार हैं।

> **संबंधित लेख:** NCPCR की सोशल मीडिया-गेमिंग गाइडलाइन्स: बच्चों की डिजिटल सुरक्षा

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. कर्नाटक के स्कूल बाल-सुरक्षा परिपत्र (2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. छात्रा के लगातार तीन दिन अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत को सूचित करना अनिवार्य है

2. बाल संरक्षण समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी

3. स्कूल परिसरों में CCTV कैमरे अनिवार्य किए गए हैं

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2. बच्चों के लिए 24x7 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है?

(a) 1091
(b) 1098
(c) 112
(d) 1078

▶ उत्तर और व्याख्या

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

स्कूल बच्चों के संरक्षण की पहली पंक्ति हैं। कर्नाटक के नए दिशानिर्देशों के संदर्भ में भारत में स्कूली बाल-सुरक्षा तंत्र की चुनौतियों और सुधार के उपायों का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए - 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: बाल अपराधों के आंकड़ों की पृष्ठभूमि में कर्नाटक का परिपत्र - संस्थागत बाल-सुरक्षा की दिशा में कदम।

मुख्य भाग में:

PCSMANTRA.COM